# मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 8 नवंबर 2023

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एमसीआईआर

## विषयवस्तु


| खंड | पृष्ठ |
|---|---|
| I. विनियमन | 1-2 |
| II. विदेशी मुद्रा प्रबंधन | 2 |
| III. वित्तीय बाज़ार | 2-3 |
| IV. ऋण प्रबंधक | 3 |
| V. मुद्रा प्रबंधन | 3 |
| VI. प्रकाशन | 3-4 |
| VII. सर्वेक्षण | 4 |
| VIII. जारी आंकड़े | 4 |


## संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

**योगेश दयाल**
**संपादक**

# I. विनियमन

## एफएटीएफ उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार

रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2023 को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार' - अक्तूबर 2023 के बारे में जानकारी दी। एफएटीएफ ने पहले धन-शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनके शासन में कार्यनीतिक कमियों वाले कतिपय क्षेत्राधिकारों की पहचान की थी और उन क्षेत्राधिकारों को बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत रखा था, जिन्होंने उनसे निपटने के लिए एफएटीएफ के साथ कार्य योजना तैयार की थी। ये क्षेत्राधिकार हैं– अल्बानिया, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कैमरून, केमैन द्वीप, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, क्रोएशिया, जिब्राल्टर, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और यमन। दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के एफ़एटीएफ़ सार्वजनिक वक्तव्य के अनुसार, एफएटीएफ की समीक्षा के आधार पर बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार की सूची में बुल्गारिया को शामिल किया गया है जबकि अल्बानिया, केमैन द्वीप, जॉर्डन और पनामा को इस सूची से हटा दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन की कार्यप्रणालियाँ

रिज़र्व बैंक ने 7 नवंबर 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन की कार्यप्रणालियों पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को एक नया व्यापक मास्टर निदेश जारी किया। आईटी सुशासन के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में कार्यनीतिक संरेखण, जोखिम प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, कार्य-निष्पादन प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता/आपदा बहाली प्रबंधन शामिल हैं। दिशानिर्देशों ने सभी विनियमित संस्थाओं को सूचना प्रणाली में किसी भी अवलोकन योग्य घटना के रूप में परिभाषित 'साइबर घटनाओं' पर कड़ी नजर रखने का निदेश दिया है। इन निदेशों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2024 है। तथापि, ये दिशानिर्देश स्थानीय क्षेत्र बैंकों और एनबीएफसी-मूल निवेश कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## कैफरल की भारत वित्त रिपोर्ट

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 नवंबर 2023 को उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) का पहला प्रमुख प्रकाशन "भारत वित्त रिपोर्ट 2023" (आईएफ़आर 2023) जारी किया। आईएफ़आर 2023, जिसका विषय "कनेक्टिंग दि लास्ट माइल" है, भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का गहन मूल्यांकन प्रदान करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## पंजीकरण प्रमाणपत्र

रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया।

इसके अलावा, 10 नवंबर 2023 को, चार एनबीएफसी और दो आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए सीओआर का अभ्यर्पण किया। रिज़र्व बैंक ने, क्रमशः भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सीओआर को निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## एनबीएफ़सी के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") को इसके दो ऋण उत्पादों 'ईकॉम' और 'इंस्टा ईएमआई कार्ड' के अंतर्गत ऋण की मंजूरी और संवितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने का निदेश दिया है।

यह कार्रवाई, कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अननुपालन, विशेष रूप से उक्त दो ऋण उत्पादों के अंतर्गत उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल ऋणों के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरणों में कमियों के कारण आवश्यक है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

**कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति**

1 नवंबर 2023 को रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2023 से श्री मनोरंजन मिश्रा को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व, श्री मिश्रा विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। श्री मिश्रा के पास भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकों और एनबीएफसी के विनियमन, बैंकों के पर्यवेक्षण तथा मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में कार्य का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने विनियामक/ पर्यवेक्षी नीतियों के निर्माण में योगदान देने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्य समूहों में सदस्य के रूप में कार्य किया है।

कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री मिश्रा i) प्रवर्तन विभाग, ii) जोखिम निगरानी विभाग और iii) बाह्य निवेश और परिचालन विभाग का कामकाज संभालेंगे।

## उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण

रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण के लिए निम्नलिखित विनियामक उपाय जारी किए।

**ए. उपभोक्ता ऋण एक्सपोज़र**

**i) वाणिज्यिक बैंकों का उपभोक्ता ऋण एक्सपोज़र**

रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के उपभोक्ता ऋण एक्सपोज़र (बकाया और साथ ही नए) जिसमें व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं, लेकिन आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषणों द्वारा प्रतिभूत ऋण शामिल नहीं हैं, के संबंध में जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

**ii) एनबीएफसी का उपभोक्ता ऋण एक्सपोज़र**

रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण के आभूषणों द्वारा प्रतिभूत ऋण और व्यष्टि वित्त/एसएचजी ऋणों को छोड़कर, खुदरा ऋण के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी (बकाया और साथ ही नए) के उपभोक्ता ऋण एक्सपोज़र पर 125 का प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

***iii) क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ***

रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और एनबीएफसी के लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्य एक्सपोज़र पर जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर क्रमशः 150 प्रतिशत और 125 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

**बी. एनबीएफसी को बैंक ऋण**

रिज़र्व बैंक ने उन सभी मामलों में, जहां एनबीएफसी की बाहरी रेटिंग के अनुसार मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम है, मूल निवेश कंपनियों को छोड़कर एनबीएफसी में एससीबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंक तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इस प्रयोजन के लिए, एचएफसी को दिए गए ऋण और एनबीएफसी को दिए गए ऋण जो मौजूदा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, को बाहर रखा गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## निदेशक मंडल का अधिक्रमण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज **अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड** के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है।

परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन हेतु श्री सत्य प्रकाश पाठक, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को "प्रशासक" नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" भी नियुक्त की है। "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य श्री वेंकटेश हेगडे (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई); श्री महेंद्र छाजेड़ (सनदी लेखाकार); और श्री सुहास गोखले (भूतपूर्व एमडी, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# विदेशी मुद्रा प्रबंधन

## चाँदी का आयात

रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2023 को निर्णय लिया कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कुछ शर्तों के अधीन योग्य ज्वैलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (IIBX) के माध्यम से चांदी के आयात के लिए ग्यारह दिनों के लिए अग्रिम भुगतान विप्रेषित की अनुमति दे सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

## भारतीय रुपया (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंक द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने संबंधी दिनांक 19 अप्रैल 2022 के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.23/21.08.008/2022-23 के पैरा 4.1 के अनुसार और दिनांक 11 जुलाई 2022 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 10 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे निर्यातक जिन्होंने एडी श्रेणी-1 बैंकों में विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खुलवाएं हैं, को रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2023 को अपने निर्यातक घटक के लिए विशेष रूप से उनके निर्यात लेनदेन के निपटान के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति दी है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# III. वित्तीय बाजार

## विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों पर रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर 2023 को सितंबर 2023 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 41वीं छमाही रिपोर्ट जारी की। 27 अक्तूबर 2023 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

| | | बिलियन अमेरिकी डॉलर |
|---|---|---|
| क्र सं | विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (i+ii+iii+iv) | 586.11 |
| 1 | विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए) | 517.50 |
| 2 | स्वर्ण | 45.92 |
| 3 | विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) | 17.91 |
| 4 | आरक्षित ट्रांच की स्थिति (आरटीपी) | 4.77 |

* अंतर, यदि कोई हो, तो वह पूर्णांकन के कारण है।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## पूर्णतः सुलभ मार्ग

रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा जारी किए गए सभी **संप्रभु हरित बॉन्ड** को तत्काल प्रभाव से **पूर्णतः सुलभ मार्ग** (एफएआर) के अंतर्गत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित किया।

यह निदेश, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIडी की धारा 45डबल्यू के अंतर्गत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हों, के प्रति पूर्वाग्रह रहित हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## सचेतक सूची

रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को अनधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्मों की सचेतक सूची में 19 संस्थाओं/ प्लेटफ़ॉर्म/ वेबसाइटों को जोड़ा, जिससे इसकी कुल संख्या 75 हो गई।

अलर्ट सूची में उन संस्थाओं के नाम शामिल हैं जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में व्यापर करने के लिए अधिकृत हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। अलर्ट सूची में उन संस्थाओं/प्लेटफ़ॉर्म/वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनधिकृत संस्थाओं/ ईटीपी को बढ़ावा देते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें ऐसी अनधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/ सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# IV. ऋण प्रबंधक

## अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2024

रिज़र्व बैंक ने 6 नवंबर 2023 को निर्णय लिया कि 07 नवंबर 2023 से 06 मई 2024 की छमाही के लिए लागू भारत सरकार **अस्थिर दर वाले बॉण्ड** 2024 (एफआरबी 2024) पर ब्याज दर 7.14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# V. मुद्रा प्रबंधन

## ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2023 को ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की स्थिति जारी की। जारी आंकड़े के अनुसार, 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में ₹2000 के बैंकनोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था, जब ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, जो अब 30 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर ₹9,760 करोड़ रह गया है। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 बैंकनोटों में से 97.26 प्रतिशत वापस आ गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# VI. प्रकाशन

## भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2022-23

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2023 को "भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2022-23" शीर्षक से अपने सांख्यिकीय प्रकाशन के आठवें संस्करण को जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आंकड़ों का प्रसार करता है।

यह प्रकाशन 1951 से 2022-23 तक की विभिन्न समयावधियों में भारतीय राज्यों में सामाजिक-जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, पर्यावरण, मूल्य और मजदूरी, उद्योग, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग और वित्तीय संकेतकों पर उप-राष्ट्रीय आंकड़ों को शामिल करता है। हैंडबुक के वर्तमान संस्करण में, मौजूदा डेटा शृंखला के अद्यतनीकरण के अलावा, निम्नलिखित संकेतकों पर 6 नई तालिकाएँ शामिल की गई हैं:

**i) सामाजिक और जनसांख्यिकीय संकेतक**

क) राज्य-वार जनसंख्या अनुमान – बहु-आयामी गरीबी सूचकांक; और

ख)राज्यवार प्राकृतिक जनसंख्या संवृद्धि दर;

**ii) स्वास्थ्य**

क)स्वास्थ्य पर राज्यवार सार्वजनिक व्यय;

**iii) पर्यावरण**

क) प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु राज्य-वार व्यय; और

ख) राज्य-वार धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) स्कोर;

**iv) बुनियादी ढांचा**

क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित राज्यवार सड़क।

विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

## आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का नवंबर 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में पाँच भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये पाँच भाषण निम्नानुसार हैं:

i) डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर ने 9 अक्तूबर 2023 को फेडरल रिज़र्व बैंक, न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क फेड सेंट्रल बैंकिंग सेमिनार में 'हरित स्वच्छ भारत की ओर' विषय पर उद्घाटन भाषण दिया।

ii) श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर ने 12 अक्तूबर 2023 को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर आयोजित सम्मेलन में 'धारणीय वित्त और वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना' पर भाषण दिया।

iii) श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 20 अक्तूबर 2023 को आर्थिक विकास संस्थान और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव में 'मूल्य और वित्तीय स्थिरता: पूरकताओं और ट्रेड-ऑफ का प्रबंधन' पर प्लीनेरी भाषण दिया।

iv) श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, ने 2 नवंबर 2023 को मुंबई में 'एक्सीलेंस एनेबलर्स' द्वारा आयोजित गेटकीपर्स ऑफ गवर्नेंस समिट में 'प्रतिबिंब: विनियमों में चुनौतियां' पर भाषण दिया।

v) गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने 9 नवंबर 2023 को इंटीट्यूट ऑफ इंडियन इकोनोमिक स्टडीज़ (आईआईईएस), टोक्यो द्वारा आयोजित 'उभरता भारत: स्थिरता और अवसरों की भूमि' पर भाषण दिया।

चार आलेख निम्नानुसार हैं:

**i) अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 की अंतिम तिमाही में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि विनिर्माण मंद हो गया है, जबकि सेवा क्षेत्र की गतिविधि, महामारी के बाद अपने विस्तार के अंत तक पहुंच गई है। आगे बढ़ते हुए, वित्तीय स्थितियों का सख्त होना वैश्विक संभावना के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है। भारत में, जीडीपी में बदलाव की गति क्रमिक रूप से 2023-24 की तीसरी

तिमाही में त्योहारी मांग प्रबल रहने के कारण उच्चतर रहने की उम्मीद है। सरकार के बुनियादी ढांचे पर व्यय, निजी पूंजीगत व्यय में बढ़ोत्तरी, स्वचालन, डिजिटलीकरण और स्वदेशीकरण से बढ़ावा मिलने से निवेश मांग आघात-सह प्रतीत होती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022-23 में 6.7 प्रतिशत और जुलाई-अगस्त 2023 में 7.1 प्रतिशत के औसत से घटकर अक्तूबर में 4.9 प्रतिशत रह गई।

**ii) बाज़ार के मन को पढ़ना: वित्तीय आंकड़ों से मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं को समझना**

यह आलेख 2016 से 2023 के दौरान मौद्रिक नीति दर में बदलाव की निकट अवधि की बाज़ार अपेक्षाओं को डिकोड करने के लिए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) दर का उपयोग करता है। इसके अलावा, यह आलेख सभी बाज़ार खंडों और परिपक्वताओं में ब्याज दर पर नीतिगत दर में प्रत्याशित और अप्रत्याशित परिवर्तनों के प्रभाव का भी विश्लेषण करता है।

**iii) भारत के विद्युत क्षेत्र में बदलाव: कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का पुन: उपयोग**

जैसा कि भारत पर्यावरणीय स्थिरता के साथ अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को संतुलित करने की दोहरी चुनौती से निपट रहा है, यह आलेख कोयला और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में लगी आस्तियों से जुड़े संभावित जोखिमों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई), जिनका इन क्षेत्रों में एक्सपोज़र है, पर उनके संभावित प्रभाव की जांच करता है।

**iv) भारत में मौद्रिक नीति संचरण: हाल की गतिकी**

मौद्रिक नीति चक्र में बदलाव की पृष्ठभूमि में, यह आलेख भारत में हालिया मौद्रिक नीति संचरण गतिकी की समीक्षा करता है। यह उधार और जमा दरों में प्रभाव विस्तार के स्तर का अनुमान लगाता है और प्रभाव विस्तार के संभावित निर्धारकों को रेखांकित करने का प्रयास करता है।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## भारतीय रिज़र्व बैंक - समसामयिक पत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2023 को अपने समसामयिक पत्रों का खंड 43, संख्या 2, 2022 जारी किया, जो उसके स्टाफ-सदस्यों के योगदान द्वारा तैयार की गई एक शोध पत्रिका है। इस अंक में तीन लेख और दो पुस्तक समीक्षाएं हैं।

**लेख:**

**i) भारत में नकद बनाम डिजिटल भुगतान लेनदेन: मुद्रा मांग विरोधाभास (पैराडॉक्स) को समझना**

नकदी और डिजिटल भुगतान के बीच कथित प्रतिस्थापन को देखते हुए, दोनों में एक साथ वृद्धि प्रतिकूल लगती है, जो मुद्रा मांग विरोधाभास को उत्पन्न करती है। यह लेख भारतीय संदर्भ में इस विरोधाभास को समझने और नकदी मांग के महत्वपूर्ण चालकों को अनुभवजन्य रूप से समझने का प्रयास करता है।

**ii) भारत में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान: क्या मशीन लर्निंग तकनीक उपयोगी हैं?**

लेखक मुद्रास्फीति और उसके निर्धारकों के बीच गैर-रेखीय संबंधों को समझने के लिए पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग करते हैं, और उनके पूर्वानुमान कार्य-निष्पादन की तुलना, एक तिमाही और चार तिमाहियों की पूर्वानुमानित अवधि के लिए पूर्व-कोविड और कोविड के बाद दोनों अवधियों के लिए लोकप्रिय पारंपरिक रैखिक मॉडल, यथा ऑटोरेग्रेसिव टाइम-सीरीज़ मॉडल, लीनियर रिग्रेशन और फिलिप्स कर्व से करते हैं।

**iii) एक नया यूनिट रूट परीक्षण मानदंड**

अनुभवजन्य साहित्य में कई मानक यूनिट रूट परीक्षण शामिल हैं। तथापि, छोटे नमूनों के लिए इन परीक्षणों का प्रभाव शक्ति अक्सर कम होता है। यह लेख किसी भी शून्य-माध्य समय शृंखला में यूनिट रूट की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए एक नया मानदंड प्रस्तावित करता है जिसमें कोई नियतात्मक प्रवृत्ति और कोई संरचनात्मक विराम नहीं है। परीक्षण को यूनिट रूट के शून्य के अंतर्गत डेटा के संभाव्यता वितरण फलन (पीडीएफ) और विकल्प के अंतर्गत डेटा के पीडीएफ के अनुपात के आधार पर विकसित किया गया है। चूँकि परीक्षण सांख्यिकी का वितरण गैर-मानक है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन तकनीक का उपयोग, परीक्षण सांख्यिकी के अनुभवजन्य वितरण को निर्धारित करने के लिए किया गया है, इसके बाद एक परिमित नमूने के लिए परीक्षण मानदंडों के प्रभाव की तुलना की जाती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# VII. सर्वेक्षण

## मुद्रास्फीति पर परिवारों की अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2023 को परिवारों की मुद्रास्फीति पर परिवारों की अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण (आईईएसएच) लॉन्च किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के 19 शहरों में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत बास्केट पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर गुणात्मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान के अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्फीति दरों पर मात्रात्मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2023 को उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) लॉन्च किया। सर्वेक्षण में देश के 19 शहरों में सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनके मनोभावों के संबंध में परिवारों से गुणात्मक प्रतिक्रिया मांगी गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# VIII. जारी आंकड़े

नवंबर 2023 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

| क्रम सं. | शीर्षक |
|---|---|
| 1 | सितंबर 2023 माह का भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े |
| 2 | अक्तूबर 2023 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश |
| 3 | वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल – जून) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े |
| 4 | वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन |
| 5 | 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) |
| 6 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – नवंबर 2023 |
| 7 | बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अक्तूबर 2023 |
| 8 | भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण |
| 9 | भारत में व्यवसाय - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |

**योगेश दयाल** द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।